engineer at Durgapur site of Instrumentation Ltd. He holds a Diploma in Electrical Engineering.

(b) As per the company's records, the above engineer does not possess wealth disproportionate to his earnings.

(c) No, Sir. The working of the site office is audited by internal audit, statutory auditors, and also the Govt. auditors. There is no report of any corrupt practices.

मध्य प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना

4943. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश में बड़े/भारी उद्योग लगाने के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) वर्ष 1991 से 1993 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने हेतु आशय-पत्रों की मंजूरी के लिए 212 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनकी तुलना में, 1-4-94 तक 66 आशय-पत्र जारी किए गए, 56 आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिए गए तथा 86 आवेदन-पत्र या तो वापस ले लिए गए या औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में परिवर्तन के लिये अध्ययन

4944. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संगठनात्मक और प्रबन्ध सम्बन्धी परिवर्तन करने के लिये कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इन परिवर्तनों को लागू करने के लिये कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) जी नहीं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पिछले तीन वर्षों में संगठनात्मक और प्रबंध परिवर्तनों के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि विभिन्न समितियां जैसे कि श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में सरकारी उद्यमों संबंधी विशेषज्ञ समिति, श्री एल. के. झा की अध्यक्षता में आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग और डा. अर्जुन सेन गुप्त की अध्यक्षता में सरकारी उद्यमों से संबंधित नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति ने क्रमशः वर्ष 1980-82, 1983-84 और 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उनकी सिफारिशों में स्वायत्तता, धारक कंपनियों का गठन, समझौता ज्ञापन आदि जैसे कई प्रकार के विषय शामिल थे। इस सम्बन्ध में सरकार ने कार्रवाई की थी और सिफारिशों को लागू किया था।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किया गया निवेश

4945. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में अब तक किये गये कुल निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उपक्रमों का वार्षिक उत्पादन कितना है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम को हुए लाभ अथवा घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इनमें से किसी उपक्रम को निजी क्षेत्र को सौंपने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) दिनांक 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 6 उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य में स्थित थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें किए गए पूंजीनिवेश, वार्षिक उत्पादन और अर्जित लाभ अथवा उठाई गई हानि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।